नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 120
दि. 02.02.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

इनकम टैक्स स्लैब जस के तस, प्रक्रियाओं में राहत और निवेश पर सख्ती का मिला-जुला संदेश

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 ने आम करदाताओं और निवेशकों के लिए एक साथ राहत और सख्ती—दोनों का संदेश दिया है। बजट से पहले जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा थी, वह था इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर की दरों और स्लैब को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और समयसीमा बढ़ाने के कई अहम प्रस्ताव जरूर किए। इससे एक ओर नौकरीपेशा और छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार और कुछ निवेश विकल्पों पर सरकार ने शिकंजा भी कसा है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में स्लैब पूरी तरह पहले जैसे ही रखे गए हैं। सालाना 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस व्यवस्था में मकान किराया भत्ता, जीवन बीमा, पीएफ, मेडिकल बीमा जैसी कटौतियों का लाभ मिलता है, इसलिए बड़ी संख्या में करदाता अभी भी इसी विकल्प को चुनना पसंद कर रहे हैं।

वहीं नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब ज्यादा हैं और टैक्स दरें क्रमशः बढ़ती हैं। इसमें 4 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स-फ्री है। 4 से 8 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 12 से 16 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत, 20 से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था उन करदाताओं के लिए आसान है जो ज्यादा छूट और कटौती का दावा नहीं करते और सरल टैक्स गणना चाहते हैं।

इस बजट की सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी समयसीमा में बदलाव को माना जा रहा है। अब रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक भरी जा सकेगी, हालांकि इसके लिए नाममात्र का शुल्क देना होगा। लंबे समय से यह शिकायत रही है कि तकनीकी दिक्कतों या दस्तावेजों की कमी के कारण कई लोग समय पर रिटर्न संशोधित नहीं कर पाते थे। इस बदलाव से नौकरीपेशा, फ्रीलांसर और छोटे व्यापारियों को खासा फायदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही रिटर्न फाइल करने की समयसीमा को भी अलग-अलग श्रेणियों के लिए चरणबद्ध किया गया है, जिससे अनुपालन प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित हो सकेगी।

बजट में मोटर एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह आयकर से मुक्त रहेगा और इस पर टीडीएस भी नहीं कटेगा। इससे दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को वास्तविक लाभ मिलेगा, क्योंकि अब मुआवजे की राशि टैक्स कटौती में नहीं फंसेगी।

विदेश पैसे भेजने वालों के लिए भी बजट में राहत का ऐलान किया गया है। पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश भेजी जाने वाली राशि पर लगने वाला टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अब 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा विदेशी टूर पैकेज पर पहले 5 और 20 प्रतिशत तक लगने वाले टीसीएस को भी घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग के उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्हें इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है।

मैनपावर सप्लाई सेवाओं को लेकर लंबे समय से टीडीएस को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। बजट में इसे स्पष्ट करते हुए इन सेवाओं को कॉन्ट्रैक्टर भुगतान के दायरे में लाया गया है, जिस पर 1 या 2 प्रतिशत की ही टीडीएस दर लागू होगी। इससे उद्योगों और सेवा क्षेत्र को राहत मिलेगी और टैक्स विवाद कम होंगे।

छोटे करदाताओं के लिए सरकार ने एक नई ऑटोमेटेड योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत नियम-आधारित प्रक्रिया के जरिए कम या शून्य टीडीएस कटौती का सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा। अब इसके लिए असेसिंग ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह Form 15G और 15H की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है, ताकि एक से ज्यादा कंपनियों में निवेश करने वाले करदाताओं को बार-बार दस्तावेज जमा न करने पड़ें।

एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी बजट में राहत दी गई है। अब टीडीएस जमा करने के लिए खरीदार को अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया अब PAN आधारित चालान के जरिए पूरी की जा सकेगी, जिससे रियल एस्टेट लेनदेन में सहूलियत बढ़ेगी। इसके अलावा विदेशी संपत्ति के खुलासे को लेकर भी एक बार की छह महीने की विशेष योजना लाने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे करदाता, छात्र, युवा पेशेवर और स्थानांतरित एनआरआई अपनी सीमित विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा बिना बड़ी परेशानी के कर सकेंगे।

हालांकि बजट में निवेशकों के लिए कुछ सख्त फैसले भी किए गए हैं। फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। इसी तरह सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर अब कैपिटल गेन टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। टैक्स-फ्री लाभ केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगा, जिन्होंने RBI से सीधे बॉन्ड खरीदे और पूरी अवधि तक रखे।

कुल मिलाकर बजट 2026 ने टैक्स स्लैब को छुए बिना प्रक्रियाओं को सरल करने और अनुपालन को आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन साथ ही सट्टा और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने का स्पष्ट संकेत भी दिया है। आम करदाता को जहां रिटर्न और टीडीएस से जुड़ी राहत मिली है, वहीं निवेशकों को अब अपने फैसले पहले से ज्यादा सोच-समझकर लेने होंगे।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूत भारत की तैयारी, रक्षा बजट में ऐतिहासिक छलांग

ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा जरूरतों और बदलते वैश्विक हालात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आम बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी है। इस बार का रक्षा बजट न केवल आंकड़ों के लिहाज से रिकॉर्ड है, बल्कि यह सरकार की उस रणनीतिक सोच को भी दर्शाता है, जिसके तहत आने वाले वर्षों में भारत को सैन्य रूप से अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 7,84,678 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब 15 प्रतिशत अधिक है। पहली बार ऐसा हुआ है जब रक्षा मद में एक ही वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई हो। पिछले पांच वर्षों के रक्षा बजट पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि सरकार ने लगातार रक्षा खर्च बढ़ाया है, लेकिन इस बार की बढ़ोतरी असाधारण है। वर्ष 2022-23 में जहां रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपये था, वह 2023-24 में बढ़कर 5.94 लाख करोड़ और 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और अब 2026-27 में यह आंकड़ा लगभग 7.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

इस निरंतर वृद्धि के पीछे सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियां, क्षेत्रीय अस्थिरता, आधुनिक युद्ध तकनीकों का तेजी से बदलता स्वरूप और हाल के सैन्य अभियानों से मिले अनुभव अहम कारण माने जा रहे हैं।

सरकार का सबसे बड़ा फोकस इस बार सेनाओं के आधुनिकीकरण पर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए आधुनिकीकरण के मद में 2,19,306 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। खास बात यह है कि इस राशि का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया जाएगा। यानी करीब 1.39 लाख करोड़ रुपये देश में ही हथियारों, सैन्य उपकरणों और आधुनिक प्रणालियों के निर्माण पर लगाए जाएंगे। इससे न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को भी मजबूत आधार मिलेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू रक्षा उद्योग, निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को नई ऊर्जा मिलेगी और भारत भविष्य में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभा सकेगा।

रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय के लिए भी निर्धारित किया गया है। इस मद में 5,53,668 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो रक्षा सेवाओं के संचालन, प्रशिक्षण, रखरखाव और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में यह राशि करीब 4.91 लाख करोड़ रुपये थी, यानी इसमें लगभग 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा संकेत है कि सरकार केवल नए हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मौजूदा सैन्य ढांचे को मजबूत और प्रभावी बनाए रखने पर भी पूरा ध्यान दे रही है।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पेंशन मद में भी बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2026-27 में पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि हर साल बढ़ रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार सेना के वर्तमान और पूर्व दोनों तरह के जवानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रही है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, पेंशन का बढ़ता बोझ एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह उस बलिदान की कीमत भी है जो सैनिक देश की सुरक्षा के लिए चुकाते हैं।

कैपिटल व्यय के तहत विमानों और एयरोइंजन की खरीद के लिए 63,733 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि नौसेना के जहाजों के लिए 25,023 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे भारतीय वायुसेना के लिए नए और आधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया को गति मिलेगी। अमेरिका से जीई एयरोइंजन की खरीद, भविष्य में अतिरिक्त राफेल विमानों की संभावित डील और स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को इससे मजबूती मिलने की उम्मीद है। नौसेना के संदर्भ में यह आवंटन नए युद्धपोतों और एक और विमानवाहक पोत के निर्माण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री ताकत और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे।

आंतरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, गृह मंत्रालय के बजट में बड़ा विस्तार

केंद्र सरकार ने आम बजट 2026-27 में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूत करने के इरादे से केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए 2,55,233.53 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन किया है। यह आवंटन न केवल पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक है, बल्कि यह सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसके तहत देश की सुरक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर सशक्त बनाया जाना है। बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2,33,210.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, ऐसे में इस बार उल्लेखनीय बढ़ोतरी को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और बढ़ती जिम्मेदारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्रीय पुलिस बलों के लिए रखा गया है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की निगरानी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। कुल आवंटन में से 1,73,802.53 करोड़ रुपये सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दिए गए हैं। इन बलों की भूमिका नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और हवाई अड्डों, औद्योगिक इकाइयों तथा संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तक फैली हुई है। बढ़ते आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा पर सतर्कता और आंतरिक कानून-व्यवस्था को देखते हुए इस आवंटन को बेहद अहम माना जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह राशि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ प्रशासनिक, विकासात्मक और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों में भी खर्च की जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि स्थायी शांति और विकास के लिए सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक मजबूती भी जरूरी है, और यह आवंटन उसी दिशा में एक कदम है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 1,348 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक जरूरतों और केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न दायित्वों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीप क्षेत्रों के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि रखी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 6,680.94 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ के लिए 5,720.17 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के लिए 2,832.70 करोड़ रुपये, लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप के लिए 1,682.35 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 3,517.88 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं, प्रशासनिक ढांचे और विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया है।

इस बजट का एक अहम पहलू जनगणना से जुड़े कार्यों के लिए किया गया प्रावधान भी है। सरकार ने जनगणना प्रक्रिया के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका पहला चरण एक अप्रैल से शुरू होगा। लंबे अंतराल के बाद होने जा रही इस जनगणना को नीति निर्माण, संसाधन वितरण और भविष्य की योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली इस प्रक्रिया के लिए अलग से बजट प्रावधान यह संकेत देता है कि सरकार इसे समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा करना चाहती है।

कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए किया गया यह आवंटन सरकार की उस रणनीति को दर्शाता है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा को राष्ट्रीय विकास की बुनियाद माना गया है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने, संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने और केंद्र शासित प्रदेशों के विकास को साथ लेकर चलने का प्रयास इस बजट में साफ झलकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस आवंटन का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग किया गया, तो देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक हो सकेगी।

रेलवे को मेगा बूस्ट, बजट 2026-27 में रफ्तार क्षमता और कनेक्टिविटी पर ऐतिहासिक दांव

नई दिल्ली। आम बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय सहारा मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल मंत्रालय के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पूंजीगत आवंटन की घोषणा की है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10.25 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के जरिए रेलवे को करीब 15,000 करोड़ रुपये और मिलेंगे। सरकार का साफ संकेत है कि आने वाले वर्षों में रेलवे केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि देश की आर्थिक गति का इंजन बनेगा। नई लाइनों के निर्माण से लेकर ट्रैक दोहरीकरण, आधुनिक कोच-इंजन, सिग्नलिंग सिस्टम और हाई-स्पीड कॉरिडोर तक, रेलवे के हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा।

बजट दस्तावेजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि कुल खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपये रहेगा। इस तरह वित्त वर्ष के अंत में रेलवे के पास करीब 3,547 करोड़ रुपये की शुद्ध आय रहने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे की आंतरिक कमाई अपने आप में इतने बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए सरकार की ओर से पूंजीगत सहायता दी जाती है। इसी के तहत नई रेल लाइनों, गेज परिवर्तन, लाइन दोहरीकरण और रोलिंग स्टॉक की खरीद जैसे कार्यों के लिए यह विशाल आवंटन किया गया है।

इस बजट में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। नई रेल लाइनों के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये, नैरो गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन के लिए 4,600 करोड़ रुपये और सिंगल लाइन मार्गों को डबल लाइन में बदलने के लिए 37,750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लोकोमोटिव, वैगन और आधुनिक कोचों की खरीद के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 7,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे ट्रेन संचालन ज्यादा सुरक्षित और समयबद्ध हो सके।

आम बजट 2026-27 की सबसे बड़ी घोषणा सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की रही, जिसे रेलवे के लिए रफ्तार के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। इन कॉरिडोर पर वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत जैसी सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें पूरी क्षमता के साथ दौड़ेंगी। मुंबई-पुणे और चेन्नई-बेंगलुरु जैसे व्यस्त और आर्थिक रूप से अहम मार्गों को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु जैसे कॉरिडोर देश के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वोत्तर हिस्सों को तेज रफ्तार से जोड़ेंगे।

इन नए हाई-स्पीड कॉरिडोर का असर सिर्फ तेज ट्रेनों तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, जब सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें अलग कॉरिडोर पर दौड़ेंगी, तो मौजूदा रेलमार्गों पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी। अभी जहां इन ट्रेनों की औसत रफ्तार करीब 55 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह बढ़कर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें 90 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलेंगी और भविष्य में इन्हें 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने की तैयारी है। इससे यात्रा समय में भारी कमी आएगी और रेल परिवहन हवाई यात्रा का सस्ता और भरोसेमंद विकल्प बनेगा।

सरकार का मानना है कि रेलवे में यह निवेश केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। रोलिंग स्टॉक के बड़े ऑर्डर से कोच फैक्ट्रियों, इंजन निर्माण इकाइयों और निजी उद्योगों को काम मिलेगा। ट्रैक नवीनीकरण, नई लाइनें और दोहरीकरण परियोजनाओं से लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मालगाड़ियों की गति और क्षमता बढ़ने से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, जिसका फायदा उद्योग, कृषि और निर्यात—तीनों क्षेत्रों को मिलेगा।

कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में रेलवे को मिला यह मेगा बूस्ट देश की कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार का फोकस साफ है—रेलवे को आधुनिक, तेज, सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देना।

संपादकीय

निष्पादन से राष्ट्र निर्माण तक: भारत के अगले दशक की निर्णायक यात्रा

पिछले दस वर्षों में भारत के आर्थिक और सामाजिक बदलाव को अक्सर जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों में समेट कर देखा गया है, लेकिन यह दृष्टि उस गहरे परिवर्तन को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाती, जो देश के भीतर घटित हुआ है। भारत का बदलाव केवल तेज़ विकास दर का नहीं, बल्कि विकास की सोच, संरचना और कार्यप्रणाली का है। एक समय जो अर्थव्यवस्था असंतुलन, सीमित राज्य क्षमता और कमजोर संस्थागत ढांचे से जूझ रही थी, वह अब पूंजीगत व्यय, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और सुदृढ़ संस्थानों के सहारे आगे बढ़ रही है। यही परिवर्तन आने वाले दशक की दिशा तय करेगा और यही यह भी बताएगा कि भारत अपने विकास को कितनी मजबूती से टिकाऊ और समावेशी बना पाता है।

इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राज्य की भूमिका में आया गुणात्मक बदलाव है। सरकार की भूमिका अब केवल नीतियां घोषित करने या कल्याण योजनाएं चलाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण और वितरण की क्षमता को सशक्त करने पर केंद्रित हुई है। डिजिटल पहचान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तेज़ और सुलभ भुगतान प्रणाली, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश ने प्रशासन को अधिक सक्षम और जवाबदेह बनाया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत कम बाधाओं और कम रिसाव के साथ नागरिकों तक पहुंचने लगा है। अब असली चुनौती इस मजबूत आधार को दीर्घकालिक उत्पादकता, आय सृजन और सामाजिक प्रगति में बदलने की है।

श्रम बाजार में आए बदलाव इस कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। डिजिटलीकरण और कर सुधारों ने लाखों व्यवसायों को औपचारिक ढांचे में आने के लिए प्रेरित किया है, जिससे हर महीने बड़ी संख्या में नए कर्मचारी औपचारिक रूप से जुड़ रहे हैं। बेरोजगारी दर का अपेक्षाकृत स्थिर रहना यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में एक बुनियादी मजबूती मौजूद है। हालांकि, केवल औपचारिक रोजगार को सफलता का पैमाना मान लेना पर्याप्त नहीं है। रोजगार की गुणवत्ता, उत्पादकता और वेतन वृद्धि अभी भी वह गति नहीं पकड़ पाई है, जो भारत की युवा आबादी की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसके भीतर मौजूद वास्तविकता अधिक जटिल है। बड़ी संख्या में महिलाएं अभी भी कम उत्पादक, कम वेतन वाले या अवैतनिक कार्यों से जुड़ी हैं। यह सामाजिक बदलाव की शुरुआत को दर्शाता है, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण की मंजिल अभी दूर है। यदि महिलाओं को कौशल-आधारित और उद्योग से जुड़े अवसरों से जोड़ा जाए, तो इसका असर केवल व्यक्तिगत आय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि घरेलू खपत, मानव विकास और सामाजिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। इसके लिए कौशल प्रमाणन, अप्रेंटिसशिप और उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण को व्यापक और प्रभावी बनाना होगा। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति उम्मीद और चेतावनी दोनों को साथ लेकर चलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हासिल की गई सफलता ने यह साबित कर दिया है कि यदि नीतिगत समर्थन स्पष्ट हो और निष्पादन निरंतर हो, तो भारत जटिल औद्योगिक क्षेत्रों में भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है। कुछ ही वर्षों में आयातक से उत्पादन और निर्यात केंद्र बनने की यह यात्रा भारत की औद्योगिक क्षमता पर लंबे समय से बनी शंकाओं को तोड़ती है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और नीतिगत स्थिरता ने इस बदलाव में निर्णायक भूमिका निभाई है।

फिर भी, यह सफलता यह भी दिखाती है कि केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। विनिर्माण का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा अभी भी सीमित है और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पूंजी-प्रधान क्षेत्रों से व्यापक रोजगार सृजन संभव नहीं। भारत की जनसांख्यिकीय संरचना श्रम-प्रधान उद्योगों में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने की मांग करती है। टेक्सटाइल, फुटवियर, खिलौना और अन्य श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति न होना यह संकेत देता है कि नीतिगत ध्यान अभी असंतुलित है। यदि इन क्षेत्रों में भी समान गंभीरता, सरल अनुपालन और बेहतर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराए जाएं, तो रोजगार सृजन की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। कारोबारी सुगमता में सुधार ने निवेश माहौल को बेहतर बनाया है, इसमें संदेह नहीं। पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाना, डिजिटल मंजूरियां और फेसलेस अनुपालन ने संचालन को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाया है। कर प्रणाली में एकीकरण से प्रशासनिक जटिलताएं घटी हैं और औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है। इसके बावजूद, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए जमीनी स्तर पर चुनौतियां बनी हुई हैं।

अदालती चौखट पर नूरा-कुश्ती की हकीकत

> जब दो पक्ष हाथ मिलाकर अदालत के सामने दिखावटी लड़ाई करते हैं, तो उसे 'कलूसिव सूट' कहते हैं। इसे 'साजिशी मुकदमा' कहना सटीक होगा।

न्यायपालिका वह पवित्र स्थान है जहां सत्य की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन आज 'कलूसिव सूट' (साजिशी मुकदमों) के जरिए इस मंदिर की गरिमा को चुनौती दी जा रही है। यह कानूनी जगत का वह अंधेरा कोना है जहां वादी और प्रतिवादी विरोधी होने का मात्र ढोंग करते हैं, जबकि हकीकत में वे एक ही 'साजिशी पटकथा' के किरदार होते हैं। जब न्याय की गुहार लगाने वाला और उसका विरोध करने वाला, दोनों ही परदे के पीछे एक हो जाएं, तो अदालत का कठघरा केवल एक रंगमंच बनकर रह जाता है। न्याय की बुनियादी अवधारणा को ठेस पहुंचती है। ऐसी कृत्रिम लड़ाइयां न केवल न्यायिक समय की बर्बादी हैं, बल्कि उन वास्तविक शोषितों का हक भी मारती हैं जो न्याय की कतार में अंतिम पायदान पर खड़े हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब दो पक्ष आपस में हाथ मिलाकर अदालत के सामने 'नूरा-कुश्ती' (दिखावटी लड़ाई) करते हैं, तो उसे कानून में 'कलूसिव सूट' कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे 'साजिशी मुकदमा' कहना ज्यादा सटीक होगा। यह एक ऐसा कृत्रिम विवाद है जहां दोनों पक्ष वास्तव में एक-दूसरे के विरोधी नहीं होते और उनके बीच कोई वास्तविक कानूनी संघर्ष नहीं होता। वे अदालत की चौखट पर सिर्फ इसलिए पेश होते हैं ताकि आपसी साजिश के जरिए एक ऐसी 'डिक्री' या सरकारी आदेश हासिल कर सकें, जिसे वे ईमानदारी के रास्ते से कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे।

हमारी भारतीय न्याय प्रणाली 'प्रतिद्वंद्वी पद्धति' पर आधारित है, जिसका मूल सिद्धांत ही यह है कि जब दो विरोधी पक्ष पूरी शिद्दत से अपनी बात और दलीलें रखेंगे, तभी सत्य छनकर बाहर आएगा। लेकिन जब विरोध ही दिखावटी हो और दोनों पक्ष 'मेज के नीचे' हाथ मिला चुके हों, तो अदालत महज एक मूकदर्शक बनकर रह जाती है। निस्संदेह, यह उस पवित्र तंत्र की तौहीन भी है जिसे समाज में न्याय की रक्षा के लिए बनाया गया है।

कानून की नजर में 'मिलीभगत' के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 40 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यदि कोई फैसला, आदेश या डिक्री 'धोखे' या 'मिलीभगत' से प्राप्त की गई है, तो उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। यह धारा एक सुरक्षा कवच है। इसके अलावा, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत अदालतों को यह अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है कि वे ऐसे मुकदमों को पहचानते ही खारिज कर दें। कानून का एक वैश्विक सिद्धांत है- धोखे से कभी भी कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं हो सकता।

भारतीय न्यायपालिका ने हमेशा से इन साजिशी मुकदमों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। इस दिशा में 'नगुबाई अम्मल बनाम बी. शमा राव' (1956) का फैसला एक नजीर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 'साजिश' और 'धोखे' के बीच के महीन अंतर को स्पष्ट किया। अदालत के अनुसार, 'फ्रॉड' में एक पक्ष दूसरे को छलता है, किंतु 'कलूज़न' में दोनों पक्ष मिलकर अदालत के साथ छल करते हैं। जब वादी और प्रतिवादी के बीच कोई वास्तविक विवाद न हो और उनका एकमात्र उद्देश्य न्याय की आड़ में किसी तीसरे पक्ष का हक मारना हो, तो वह पूरी तरह 'साजिश' है। इसी प्रकार, 'रूपचंद गुप्ता बनाम रघुवंश कुमार' (1964) में अदालत ने आगाह किया कि यदि डिक्री का उद्देश्य किसी किराएदार या हकदार का अधिकार मारना है, तो वह डिक्री बातिल (शून्य) होगी। इन फैसलों से स्पष्ट है कि न्याय के सिंहासन पर बैठी अदालतें केवल कागजी सबूतों को नहीं तौलतीं, बल्कि मुकदमों के पीछे छिपी बदनियती को पहचानने की कुव्वत भी रखती हैं।

लोग ऐसा जोखिम अक्सर निजी स्वार्थ के लिए उठाते हैं, जैसे टैक्स चोरी, बैंक के कर्ज से बचना या अवैध कब्जा करना। इसका सबसे बड़ा खमियाजा उस 'तीसरे पक्ष' को भुगतना पड़ता है जो अनजाने में अपना कानूनी हक खो देता है; जैसे पिता-पुत्र की मिलीभगत बैंक के अधिकार को खत्म कर सकती है। यहां 'मैत्रीपूर्ण मुकदमे' (धारा 90, नागरिक प्रक्रिया संहिता) और 'साजिशी मुकदमे' के बीच की 'कुत्सित मंशा' को समझना लाजिमी है। जहां मैत्रीपूर्ण वाद कानूनी स्पष्टता के लिए होते हैं, वहीं साजिशी मुकदमे का उद्देश्य 'अधिकार का अपहरण' करना होता है। इसी महीन लकीर को पहचानना ही एक न्यायाधीश की असल परीक्षा है।

एक वकील के लिए उसका पेशा केवल जीविका नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। वकीलों को यह समझना होगा कि वे 'ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट' हैं, न कि किसी साजिश के पटकथा लेखक। यदि कोई अधिवक्ता जानते हुए भी ऐसे फर्जी मुकदमों का हिस्सा बनता है, तो बार काउंसिल को ऐसे सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस खतरे को टालने के लिए सजग 'न्यायिक सक्रियता' अनिवार्य है। अदालतों को मुकदमों के पीछे छिपी मंशा को भांपना होगा; जहां प्रतिवादी बिना किसी प्रतिरोध के सब स्वीकार कर ले, वहां न्यायपीठ को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारी आर्थिक दंड की ऐसी नजीर पेश करनी होगी, जो भविष्य के लिए सबक बने। साथ ही, उन 'तीसरे पक्षों' के लिए कानूनी राह आसान करनी होगी, जो इन बंद कमरों की साजिशों के असली शिकार होते हैं।

न्यायपालिका की वास्तविक ताकत उसकी पारदर्शिता और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा में निहित है। हमें एक ऐसी न्यायिक संस्कृति विकसित करनी होगी जहां चालाकी की जगह सच्चाई का बोलबाला हो। जैसा कि कहा गया है, 'न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए'। जब हम इन साजिशी मुकदमों का पर्दाफाश करेंगे, तभी हम एक पारदर्शी-मजबूत न्याय प्रणाली का निर्माण कर पाएंगे।

प्रेरणा

समय की कसौटी पर खरा उतरता धैर्य

मनुष्य के जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब परिस्थितियां उसकी क्षमता से कहीं बड़ी दिखाई देती हैं। हर तरफ अनिश्चितता होती है, डर होता है और असफलता की आशंका मन को जकड़ लेती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति धैर्य, संयम और आत्मविश्वास का हाथ थामे रखता है, वही इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाता है। यह लेख उसी सत्य को रेखांकित करता है कि सच्चा परिवर्तन शोर, जल्दबाजी या आवेश से नहीं, बल्कि शांत मन और दृढ़ संकल्प से जन्म लेता है।

इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, वे एक ही रात में नहीं हुए। उनके पीछे वर्षों का धैर्य, असंख्य असफलताएं और अटूट विश्वास छिपा होता है। अक्सर लोग केवल सफलता का अंतिम दृश्य देखते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने की लंबी और कठिन यात्रा को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तविकता यह है कि हर बड़ी उपलब्धि से पहले व्यक्ति को स्वयं से लड़ना पड़ता है। अपने डर, संदेह और अधीरता को हराकर आगे बढ़ना पड़ता है। यही आंतरिक संघर्ष किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है।

आज की तेज रफ्तार दुनिया में धैर्य को कमजोरी समझ लिया गया है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, बिना यह सोचे कि मजबूत नींव के बिना ऊंची इमारत खड़ी नहीं हो सकती। सफलता के इस भ्रम में कई बार लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, जो भविष्य में भारी नुकसान का कारण बनते हैं। इसके विपरीत, जो लोग परिस्थितियों को समझकर, समय की मांग को पहचानकर और सोच-समझकर कदम उठाते हैं, वे धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सफलता की ओर बढ़ते हैं। उनका रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन मंजिल अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है।

धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए निरंतर प्रयास करना है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति भावनाओं के आवेग में बहने के बजाय विवेक से काम लेता है। जब चारों ओर तनाव और भ्रम होता है, तब शांत मन से लिया गया निर्णय सबसे प्रभावी सिद्ध होता है। ऐसे ही निर्णय कठिन परिस्थितियों में दिशा देते हैं और संकट को अवसर में बदल देते हैं। धैर्य व्यक्ति को यह शक्ति देता है कि वह असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीख के रूप में स्वीकार कर सके।

विश्वास इस धैर्य का आधार होता है। जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है, तब वह कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में देखता है। यह विश्वास केवल स्वयं पर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया पर भी होना चाहिए, जिससे होकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन यदि विश्वास बना रहे तो व्यक्ति टूटता नहीं। वह जानता है कि हर छोटा कदम उसे उसके उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। यही निरंतरता अंततः बड़े बदलाव का कारण बनती है।

साहस धैर्य और विश्वास का स्वाभाविक परिणाम होता है। जब मन स्थिर होता है और उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब व्यक्ति जोखिम उठाने से नहीं घबराता। यह साहस अंधा नहीं होता, बल्कि सोच-समझकर लिया गया निर्णय होता है। ऐसा साहस व्यक्ति को भीड़ से अलग करता है। जहां अधिकांश लोग परिस्थितियों को दोष देकर पीछे हट जाते हैं, वहीं साहसी व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में संभावनाएं तलाशता है। यही दृष्टिकोण उसे नई राह बनाने की क्षमता देता है।

जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक या पेशेवर हर क्षेत्र में यही सिद्धांत लागू होता है। चाहे कोई विद्यार्थी हो, जो बार-बार असफल होने के बावजूद पढ़ाई जारी रखता है, या कोई उद्यमी हो, जो नुकसान के बाद भी अपने सपने पर काम करता रहता है—हर जगह धैर्य ही निर्णायक भूमिका निभाता है। यह धैर्य व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने देता। वह समझ जाता है कि असली नियंत्रण उसके विचारों और प्रतिक्रियाओं पर है।

समाज में भी बदलाव इसी मानसिकता से आता है। जब लोग आवेश में नहीं, बल्कि समझदारी से समस्याओं का समाधान खोजते हैं, तब स्थायी परिवर्तन संभव होता है। इतिहास में कई आंदोलन ऐसे रहे हैं जिन्होंने हिंसा या जल्दबाजी के बजाय संयम और दृढ़ता को अपना हथियार बनाया। उन्होंने समय लिया, संघर्ष किया और अंततः अपने लक्ष्य को हासिल किया। यह साबित करता है कि धैर्य केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति भी बन सकता है।

आज के समय में जब हर ओर अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा और तनाव है, तब धैर्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता और हर सवाल का जवाब एक ही बार में नहीं मिलता। कभी-कभी रुककर सोचना, खुद को संभालना और फिर आगे बढ़ना ही सबसे सही रणनीति होती है। यही समझ व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाए रखती है।

अंततः, धैर्य, विश्वास और साहस का यह मेल ही जीवन को सार्थक बनाता है। यह हमें सिखाता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता पैदा कर लेता है, तब बाहरी तूफान भी उसे डिगा नहीं पाते। यही वह अवस्था है जहां से इतिहास बदलता है और भविष्य नई दिशा लेता है।

बड़े और ठोस सुधारों का इंतजार, कायम रहना चाहिए रिफॉर्म का सिलसिला

संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने यह रेखांकित किया कि तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, लेकिन यदि विकसित भारत के लक्ष्य को सचमुच पाना है तो इन चुनौतियों से पार पाना होगा और चुनौतियों से पार तभी पाया जा सकता है, जब आमूलचूल सुधार किए जाएंगे और उन पर तेजी से अमल भी किया जाएगा।

यह ठीक है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति मिलेगी, लेकिन देखना यह है कि सभी आवश्यक सुधार हो पाते हैं या नहीं? क्या यह उम्मीद की जाए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में व्यापक सुधारों की घोषणा करेंगी। वास्तव में केवल बजट में ही कुछ बड़े और बुनियादी सुधारों की घोषणा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सुधारों का सिलसिला कायम रहना चाहिए।

इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि आर्थिक विकास को केवल सरकारी प्रयासों से गति नहीं दी जा सकती। आर्थिक सर्वेक्षण साफ तौर पर यह कह रहा है कि विकास को अपेक्षित गति देने के लिए निजी क्षेत्र को अपनी सक्रियता दिखानी होगी। विश्व भर में आर्थिक मोर्चे पर जैसी उथल-पुथल हो रही है और अनिश्चितता का जैसा वातावरण है, उसमें सरकार और निजी क्षेत्र को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। निजी क्षेत्र उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसते हुए नहीं दिख रहा है, जो अर्थव्यवस्था के समक्ष आ खड़ी हुई हैं। जब आर्थिक समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि निजी क्षेत्र अब केवल एक भागीदार नहीं है, बल्कि 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर को बनाए रखने के लिए मुख्य इंजन है, तब उसे इसी भूमिका में आना होगा और देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने के साथ शोध एवं विकास में निवेश करना होगा। उसे तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ना होगा और उत्पादकता के मामले में भी सुधार करना होगा। इससे ही हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय बनेंगे और उनकी विश्व में मांग बढ़ेगी। आज ऐसा नहीं है और इसी कारण आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि कई आयात अवांछनीय हैं। यह भी स्पष्ट है कि अभी देश में उच्चतम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस पर गौर किया जाए कि आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि दोयम दर्जे की गुणवत्ता की वस्तुएं बनाने वालों को संरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। यदि वे प्रतिस्पर्धी नहीं बनते तो उन्हें संरक्षण देना समस्या को बढ़ाना ही है। आज जब स्वदेशी की बातें हो रही हैं, तब उस सामग्री के आयात का कोई औचित्य नहीं, जिसे देश में निर्मित किया जा सकता है। देश की आर्थिक सूरत बदलने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकारें भी आर्थिक माहौल को बदलने के लिए वैसी ही तत्परता दिखाएं, जैसी केंद्र सरकार दिखा रही है। उद्योग-धंधों का सही से विकास तभी हो सकता है, जब राज्य सरकारें अनुकूल माहौल निर्माण करने के लिए एक-दूसरे से होड़ करती दिखेंगी। अभी तीन-चार राज्य ही इसमें शामिल दिखते हैं। कई तो ऐसा दिखाते हैं, जैसे देश का आर्थिक विकास करना और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना केवल केंद्र सरकार का काम है।

यह भी ठीक नहीं कि राज्य सरकारें आर्थिक मामलों में राजनीति करती दिखें। कुछ राज्य सरकारें जिस तरह राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने को लेकर लापरवाह दिखती हैं, वह शुभ संकेत नहीं।

जैसे केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी नौकरशाही आर्थिक विकास की बाधाओं को दूर करने का काम प्राथमिकता के आधार पर करे, वैसे ही राज्य सरकारों को भी अपनी नौकरशाही के रुख-रवैये को बदलना होगा। आज नौकरशाही अड़ंगे लगाने और उद्योग-व्यापार जगत को हतोत्साहित करने के लिए ही अधिक जानी जाती है। उसके ऐसे ही रवैये के कारण कारोबारी सुगमता केवल कागजों पर ही बेहतर नजर आती है।

सच यह है कि नए उद्योग-धंधे लगाना अभी भी जटिल और समय खपाऊ बना हुआ है। नौकरशाही के प्रतिकूल रवैये के कारण अपने देश में विकास के कई काम इस तरह होते हैं कि उनसे संसाधनों की बर्बादी होती रहती है। यह भी एक तथ्य है कि नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बना हुआ है। औसत नौकरशाहों का रवैया खुद को माई-बाप मानने वाला है। जवाबदेही के अभाव के चलते स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं।

आर्थिक समीक्षा में उद्यमी राज्य की जिस अवधारणा का उल्लेख किया गया है, उसकी पूर्ति तब होगी, जब शासन-प्रशासन के लोग पारंपरिक तरीके से काम करने के बजाय तेजी से निर्णय लेंगे, जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करेंगे और नवाचार को बढ़ावा देंगे। अनिश्चितता के दौर में ऐसा करना और भी आवश्यक हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रवृत्ति का अभाव ही दिखता है। नौकरशाही में जोखिम लेने की क्षमता विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि जहां उसे बेवजह की कानूनी प्रक्रियाओं से बचाने के उपाय किए जाएं, वहीं भ्रष्टाचार को सहन न किया जाए।

एक लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, लेकिन अपने देश में शहरी ढांचे में कोई उल्लेखनीय सुधार आने के बजाय वह चरमराता हुआ ही दिखता है। यह समझने में देर नहीं की जानी चाहिए कि केवल फुटपाथ ठीक करने या दो-चार फ्लाईओवर बना देने से शहरों का ढांचा सुधरने वाला नहीं है। अभी शहरी विकास के नाम पर ऐसे ही काम हो रहे हैं और इसी कारण आर्थिक समीक्षा में शहरों के असंतुलित विकास पर चिंता व्यक्त की गई है। शहरों का विकास इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे आधारभूत ढांचे का विकास होने के साथ ही शहरी जीवन सुविधाजनक हो। ऐसे माहौल में ही शहरों में उद्योग-धंधे सही तरह विकसित होंगे।

अभियान

आस्था की अग्निपरीक्षा में अडिग विश्वास: माघी पूर्णिमा पर संगम तट पर उमड़ा

कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर की चुनौती भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं की आस्था को रोक नहीं सकी। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर श्रद्धा का ऐसा जनसैलाब उमड़ा, जिसने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनमानस में आस्था केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है। रविवार की सुबह आठ बजे तक करीब 90 लाख श्रद्धालुओं ने संगम और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। यह दृश्य केवल संख्या का नहीं था, बल्कि उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतिबिंब था, जो सदियों से भारत की आत्मा में प्रवाहित होती रही है।

शनिवार की आधी रात से ही मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग अलसुबह घरों, धर्मशालाओं और अस्थायी शिविरों से निकल पड़े। ठिठुराती हवा और कोहरे की चादर के बीच जब श्रद्धालु गंगा तट की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके चेहरों पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं, बल्कि एक अजीब सा संतोष और उत्साह दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आस्था ने शीत को पराजित कर दिया हो। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे—हर वर्ग के लोग गंगा स्नान के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे।

माघी पूर्णिमा का स्नान माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। खासकर उन कल्पवासियों के लिए, जिन्होंने पिछले एक महीने से संगम तट पर कठिन नियमों और संयम के साथ कल्पवास किया है, यह स्नान आध्यात्मिक यात्रा का चरम बिंदु होता है। जिला प्रशासन के अनुसार, मेला क्षेत्र में लगभग पांच लाख कल्पवासी एक महीने तक निवास कर रहे थे, जिनका कल्पवास माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ संपन्न हुआ। इस कारण बड़ी संख्या में उनके परिजन भी प्रयागराज पहुंचे, ताकि वे अपने स्वजनों को इस पुण्य अवसर के बाद घर वापस ले जा सकें। इससे श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक वृद्धि देखने को मिली।

सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता कम होने के बावजूद स्नान प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलती रही। सभी प्रमुख और छोटे घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही थीं, लेकिन कहीं भी अव्यवस्था या अफरा-तफरी का दृश्य नहीं था। लोग संयम के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हर डुबकी के साथ 'हर हर गंगे' और 'हर हर महादेव' के जयकारे गूंज रहे थे, जिससे पूरा मेला क्षेत्र भक्तिरस में सराबोर हो गया था।

इस विशाल आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। सभी घाटों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें पूरी तरह सतर्क अवस्था में तैनात रहीं। नाविकों और प्रशिक्षित गोताखोरों को भी हर घाट पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। गंगा की तेज़ धारा और ठंडे पानी के बावजूद स्नान प्रक्रिया बिना किसी बड़ी घटना के संपन्न हुई, जो प्रशासनिक तैयारी और समन्वय का प्रमाण है।

मेला क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया गया। जगह-जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी। अधिकारी लगातार मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे और किसी भी समस्या पर तुरंत कार्रवाई की जा रही थी। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, बल्कि श्रद्धालुओं में भी विश्वास बना रहा कि वे सुरक्षित माहौल में अपनी आस्था का निर्वहन कर सकते हैं।

माघ मेले की विशेषता केवल स्नान तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा आयोजन है, जहां आध्यात्म, संस्कृति और सामाजिक जीवन एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। संगम तट पर साधु-संतों के प्रवचन, अखाड़ों की छावनियां, यज्ञ-हवन और भजन-कीर्तन का वातावरण पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। माघी पूर्णिमा के दिन यह वातावरण और भी गहन हो गया। स्नान के बाद श्रद्धालु दान-पुण्य करते दिखाई दिए। अन्नदान, वस्त्रदान और जरूरतमंदों की सहायता को इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है, और लोगों ने खुले दिल से इसमें भाग लिया।

कल्पवासियों के लिए यह दिन विशेष भावनात्मक महत्व रखता है। एक महीने तक सादगी, संयम और नियमों के साथ बिताया गया समय माघी पूर्णिमा पर पूर्णता को प्राप्त करता है। कई कल्पवासी भावुक होकर संगम तट को नमन करते दिखाई दिए। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण का अनुभव होता है। कल्पवास के दौरान बनी मित्रताएं, साझा अनुभव और आध्यात्मिक साधना की स्मृतियां उनके साथ जीवन भर के लिए चली जाती हैं।

प्रयागराज का माघ मेला यह भी दिखाता है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकती हैं। एक ओर हजारों वर्षों पुरानी धार्मिक परंपराएं जीवंत हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक दक्षता उन्हें सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में जुटी हुई है। यह संतुलन ही इस आयोजन की सबसे बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना और बिना किसी बड़ी अव्यवस्था के स्नान का संपन्न होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ माघ मेले का एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हो गया है, लेकिन श्रद्धा की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ माघ मेला अपने समापन की ओर बढ़ेगा। तब तक संगम तट पर आस्था का यह प्रवाह बना रहेगा। हर दिन यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं, बल्कि अपने साथ विश्वास, उम्मीद और आध्यात्मिक शांति भी लेकर लौटते हैं।

कुल मिलाकर, माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज में उमड़ा यह जनसागर केवल एक समाचार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर है। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, आस्था की ऊष्मा उसे पराजित कर सकती है। गंगा में लगाई गई हर डुबकी केवल जल में प्रवेश नहीं, बल्कि उस परंपरा से जुड़ाव है, जिसने सदियों से लोगों को एक सूत्र में बांधे रखा है। यही कारण है कि कड़ाके की ठंड भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक सकी और संगम तट पर विश्वास की यह अद्भुत कथा एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

आम बजट 2026-27: यूपी–बिहार के लिए विकास की नई रेखा, कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार तक बदलेगी तस्वीर

जीएनएस)। लखनऊ/पटना/वाराणसी। केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में किए गए बड़े प्रावधानों से दोनों राज्यों की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट में जहां उत्तर प्रदेश को हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क और शहरी विकास के बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, वहीं बिहार को जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स हब और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की सौगात दी गई है। राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि पूर्वी भारत के उत्थान की स्पष्ट रूपरेखा है।

उत्तर प्रदेश के लिए बजट में विकास का पिटारा खोल दिया गया है। वाराणसी को दो बड़े हाई-स्पीड ग्रीन रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच बनेगा, जिससे राजधानी और पूर्वांचल के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। दूसरा कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित है, जो पूर्वी भारत को सीधे जोड़ने का काम करेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को लगभग 1,500 किलोमीटर लंबाई के हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी।

काशी के लिए एक और बड़ी घोषणा गंगा नदी में चलने वाले जहाजों और कार्गो वेसल्स की मरम्मत के लिए आधुनिक सेंटर की स्थापना को लेकर की गई है। इससे जलमार्ग आधारित परिवहन को मजबूती मिलेगी और वाराणसी एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरेगा। इसके साथ ही समुद्री विमान संचालन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना और राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार की घोषणा से प्रदेश की नदियों पर आधारित अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। यूपी में पहले से ही पांच नदियों पर जलमार्ग से जुड़े काम चल रहे हैं, जिन्हें अब और गति मिलने की उम्मीद है।

शहरी विकास के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए देशभर में 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यूपी के ऐसे 25 शहर—जिनमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, नोएडा, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, अलीगढ़,

मुरादाबाद और उन्नाव जैसे प्रमुख नगर शामिल हैं—इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। बेहतर सड़कें, परिवहन, जलापूर्ति, सीवरेज और स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाओं से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट ने मजबूत संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है, जिससे दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के मामलों में समय पर इलाज संभव होगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए नए गर्ल्स हॉस्टल, कौशल विकास के लिए आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी स्टेम संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव भविष्य की पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को मंजूरी मिलना उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित यह पार्क न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा छोटे तीर्थ स्थलों के विकास की योजना के तहत सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को भी नई पहचान मिलेगी।

हैंडलूम और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की शुरुआत से उत्तर प्रदेश की एक जिला, एक उत्पाद योजना को नई ताकत मिलेगी। इससे कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों की आय बढ़ेगी और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह 145 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को समेटने वाला दस्तावेज है, जो विकसित भारत की दिशा में ठोस कदम साबित होगा। बिहार के लिए भी आम बजट 2026-27 उम्मीदों से भरा हुआ है। राज्य को जलमार्ग, हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य माल ढुलाई की लागत को कम करना और बिहार को पूर्वी भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाना है। गंगा, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन नदियों के जल नेटवर्क को मजबूत करने की योजना से राज्य में आंतरिक जल परिवहन को नई दिशा मिलेगी। पटना में जहाजों और कार्गो वेसल्स की मरम्मत और तकनीकी सेवाओं के लिए उच्चस्तरीय सेंटर की स्थापना से उद्योग और व्यापार को बड़ा सहारा मिलेगा। बजट में बिहार के सामाजिक ढांचे पर भी खास ध्यान दिया गया है। प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण की योजना से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। शहरी विकास से जुड़े प्रावधानों से राज्य के शहरों को आधुनिक स्वरूप देने में मदद मिलेगी। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस से बिहार को औद्योगिक निवेश, आधारभूत ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को देश के दीर्घकालीन विकास की मजबूत आधारशिला बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा से देश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी। विशेष रूप से वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, जबकि पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना से राज्य के उद्योग, व्यापार और निर्यात गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

कुल मिलाकर आम बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विकास की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और जलमार्ग जैसे क्षेत्रों में किए गए बड़े निवेश से न केवल आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो आने वाले वर्षों में यूपी और बिहार देश के विकास इंजन के रूप में उभर सकते हैं।

“मेरा टिकट, मेरी शान - विकसित भारत के लिए मेरा योगदान” अभियान के अंतर्गत जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर जन-जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा डिजिटल रेलवे सेवाओं के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री तरूण जैन के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से चलाए जा रहे “मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान” अभियान के अंतर्गत 01 फरवरी, 2026 (रविवार) को जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर जन-जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जूनागढ़ के माननीय विधायक श्री संजयभाई कोराडीया, महापौर श्री धर्मेश पॉशिया, उप-महापौर श्री आकाश कटारा, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री पुनीत शर्मा, भाजपा उपाध्यक्ष गीताबेन, भाजपा दंडक श्री कल्पेश अजवानी, बक्शी पंच

प्रदेश मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री जे. के. चावड़ा सहित अन्य स्थानीय गणमान्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विद्यालयी विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने यात्रियों एवं विद्यार्थियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के महत्व से अवगत कराया और यह संदेश दिया कि टिकट लेकर यात्रा करना केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से आम जनता और विद्यार्थियों में जिम्मेदार यात्रा की भावना को सुदृढ़ किया गया।

वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को रेलवन (RailOne) ऐप की विस्तृत जानकारी दी गई। ऐप के प्रमुख लाभों—जैसे आसान टिकट बुकिंग, ट्रेनों की रीयल-टाइम जानकारी तथा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न रेलवे सेवाओं—के बारे में विस्तार से बताया गया और डिजिटल सेवाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने, डिजिटल रेलवे सेवाओं को अपनाने तथा एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल रेलवे प्रणाली के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विद्यालयी बच्चों ने जागरूकता नारे लगाकर यात्रियों से “टिकट लेकर ही यात्रा करें” की अपील की। इस अभियान से जहाँ यात्रियों में रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी, वहीं विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों, ईमानदार यात्रा और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई।

यह जन-जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी अनुभव सिद्ध हुआ, जिससे उनमें आत्मविश्वास के साथ-साथ समाज के प्रति सकारात्मक भागीदारी की भावना का विकास हुआ। पश्चिम रेलवे द्वारा बच्चों को इस अभियान का हिस्सा बनाकर भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण की दिशा में एक सार्थक पहल की गई।

गुजरात में किसानों की आवाज दबाने की साजिश बेनकाब, केजरीवाल ने जमानत को बताया सच की जीत

गुजरात। राज्य में किसानों की आवाज को दबाने के प्रयासों के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट से राहत मिलने की खबर ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम सहित अन्य कई लोगों को लंबे समय से जेल में रखा गया था, क्योंकि उन्होंने गुजरात के किसानों के हितों के लिए आवाज उठाई थी। अब इन नेताओं को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे “सच की जीत” बताया और सोशल मीडिया पर स्पष्ट संदेश दिया कि भाजपा की दमनकारी नीतियों के बावजूद न्याय और सत्य की विजय होती है।

अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “सत्यमेव जयते। गुजरात के किसानों की आवाज बने हमारे नेता राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य को कोर्ट से जमानत मिलना सच की जीत है। भाजपा ने किसानों की आवाज दबाने के लिए जुल्म और साजिश का सहारा लिया, लेकिन यह कोर्ट में बेनकाब हो गया। आम आदमी पार्टी कभी भी डर, जेल और दमन के आगे नहीं झुकेगी। यह लड़ाई गुजरात के किसानों और उनके सम्मान की है, और हम इसे जीत कर रहेंगे।”

राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम, जो लंबे समय से किसानों के मुद्दों को उजागर करते आए हैं, को जेल में रखने का मुख्य आरोप था कि उन्होंने सरकार की नीतियों और कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके समर्थकों का कहना है कि यह कदम किसानों की आवाज को दबाने के लिए राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। जमानत मिलने के बाद किसान समुदाय में खुशी की लहर है और उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी समस्याओं को न्यायपूर्ण तरीके से उठाया जाएगा।

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा की जेल, डर और दमन की राजनीति गुजरात के किसानों को कभी भी झुका नहीं सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। यह लड़ाई केवल राजनैतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह गुजरात और उसके किसानों के सम्मान की लड़ाई है।

गुजरात के किसान लंबे समय से सिंचाई, फसल मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसे मुद्दों पर संघर्षरत रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा किसानों की आवाज को उठाया है और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है। अब कोर्ट ने जमानत देकर यह संदेश दिया है कि लोकतंत्र में सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है।

राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम के समर्थकों ने कहा कि जमानत मिलने के बाद वे किसानों के हितों की लड़ाई को और अधिक सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएंगे। किसान समुदाय का मानना है कि यह न केवल उनके नेताओं के लिए, बल्कि पूरे गुजरात के किसानों के लिए एक बड़ी जीत है।

इस घटना ने राज्य में राजनीतिक हलचल भी पैदा कर दी है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा सरकार की नीतियों की विफलता और किसानों के प्रति उसकी उदासीनता के रूप में देखा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे एक नए राजनीतिक संदेश के रूप में पेश किया है कि पार्टी किसान हितों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और न्याय के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी।

राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम की जमानत को लेकर कोर्ट ने साफ किया कि आरोपों की जांच पूरी तरह से न्यायसंगत तरीके से की जाएगी और किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर फैसला नहीं लिया जाएगा। इससे किसानों और पार्टी समर्थकों में न्याय के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएगी। उनके अनुसार, किसानों की आवाज दबाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, और पार्टी उनके साथ मिलकर हर संघर्ष में न्याय सुनिश्चित करेगी।

कुल मिलाकर, यह मामला न केवल गुजरात के किसानों के अधिकारों की लड़ाई है, बल्कि यह लोकतंत्र और न्याय की जीत का प्रतीक भी बन गया है। जमानत मिलने के बाद किसान नेताओं को सक्रिय होकर अपने समुदाय के हितों के लिए काम करने का अवसर मिलेगा, और आम आदमी पार्टी इसे राज्य और देश में किसानों के सम्मान की लड़ाई के रूप में आगे बढ़ाएगी।

केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र को करोड़ों की विशाल सौगात बुलेट ट्रेन और हाई-स्पीड कॉरिडोर से मिलेगी नई गति

नई दिल्ली/मुंबई। केंद्रीय बजट 2026-27 ने महाराष्ट्र के लिए विकास और आर्थिक प्रगति के लिहाज से अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि राज्य को कुल लगभग एक लाख करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 98,306 करोड़ रुपये और विशेष विकास परियोजनाओं के लिए 12,355 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस बजट को सीएम ने महाराष्ट्र की आर्थिक मजबूती और भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

सबसे प्रमुख प्रावधानों में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए 6,103 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। यह परियोजना न केवल मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय को उल्लेखनीय रूप से घटाएगी, बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे को भी नई गति प्रदान करेगी। इसके साथ ही मुंबई मेट्रो के लिए 1,702 करोड़ रुपये, पुणे मेट्रो के लिए 517.74 करोड़ रुपये, एमयूटीपी-3 परियोजना के लिए 462 करोड़ रुपये और समृद्धि महामार्ग पर आईटीएस (इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम) के लिए 680.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन सभी प्रावधानों के माध्यम से शहरों में सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता, गति और सुविधा में सुधार आएगा, जो लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा।

बजट ने केवल शहरों तक सीमित नहीं रहते हुए ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा है। कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए 646.24 करोड़ रुपये, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में सौर ऊर्जा करण के लिए 207.10 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र एग्री-बिजनेस परियोजना के लिए 167.28 करोड़ रुपये और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 378.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, मानव विकास के लिए कौशल और एप्लाइड नॉलेज परियोजना के लिए 313.65 करोड़ रुपये, समावेशी विकास और इकोनॉमिक क्लस्टर के लिए 283.77 करोड़ रुपये, जिलों में संस्थागत क्षमता

विकास के लिए 240.90 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र टर्शरी केयर एवं मेडिकल शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिए 385.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये सभी परियोजनाएं न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि बजट से ग्रोथ हब के रूप में मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR), पुणे और नागपुर को सीधा लाभ होगा। हाई-स्पीड कॉरिडोर जैसे मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद रेल नेटवर्क राज्य की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विशेष रूप से मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के आर्थिक परिदृश्य में सुधार होगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास और जिला अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

हालांकि, मुंबई में नागरिकों और यात्रियों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में शहर के लोकल रेल नेटवर्क, ट्रैफिक, किफायती आवास और रोजमर्रा की यात्रा में सुधार जैसी ठोस घोषणाएं अपेक्षित थीं। मुंबई एमएमआर में रोजाना 75–80 लाख यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन लोकल ट्रेनों की भीड़, दुर्घटनाओं और अतिरिक्त सेवाओं की मांगों को बजट में पर्याप्त महत्व नहीं मिला। यात्रियों ने चिंता जताई कि बुलेट ट्रेन और हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलने से एशिया के सबसे व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र के लिए आवंटित 12,355 करोड़ रुपये और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के 98,306 करोड़ रुपये राज्य की आर्थिक और बुनियादी ढांचे की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हाई-स्पीड कॉरिडोर, मेट्रो परियोजनाएं और ग्रामीण विकास प्रावधान भविष्य में रोजगार सृजन, उद्योगिक निवेश और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से राज्य को नई दिशा देंगे।

साथ ही, राज्य के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में निवेश, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक पहलुओं पर फोकस राज्य के दीर्घकालीन विकास की नींव रखेगा। बजट में किए गए निवेश से न केवल आर्थिक वृद्धि होगी, बल्कि नागरिक जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। केंद्र सरकार का स्पष्ट संदेश गया है कि राज्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

हालांकि शहरों में रोजमर्रा की नागरिक जरूरतों, विशेष रूप से मुंबई में लोकल ट्रेनों की भीड़ और ट्रैफिक जैसे मुद्दों को संतुलित तरीके से आगे लाने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। बजट ने विकास और बुनियादी ढांचे की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं, लेकिन शहरों के दैनिक जीवन में सुधार के लिए आगे और ठोस उपायों की आवश्यकता बनी हुई है। यह बजट महाराष्ट्र के लिए विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक व्यापक और दीर्घकालीन योजना का संकेत देता है।

जौनपुर में कोडीन कफ सिरप तस्करी का मामला गंभीर, फरार आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

जौनपुर। जनपद जौनपुर में कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी का मामला अब और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच में सहयोग नहीं करने वाले 22 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है और संकेत दिया है कि अगर वे जल्द अदालत या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। यह कदम मामले की गंभीरता को दर्शाता है और तस्करी के बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने की ओर सरकार की स्पष्ट चेतावनी है।

एसआईटी की जांच में यह सामने आया है कि वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल और उनके पिता भोला जायसवाल ने रांची स्थित शैली ट्रेडर्स फर्म से कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी खेप खरीदकर जौनपुर समेत आसपास के जिलों में सप्लाई की थी। इस आपूर्ति से जुड़े मामलों में पहले ही भोला जायसवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शुभम जायसवाल और अन्य आरोपी अभी फरार हैं। एसआईटी प्रमुख एवं सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता ने बताया कि आरोपियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन किसी ने भी जांच में सहयोग नहीं किया। इसी कारण शनिवार को 22 फरार आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।

जांच में शामिल आरोपियों की पहचान वाराणसी, सहारनपुर और जौनपुर के विभिन्न इलाकों से हुई है। एसआईटी ने कहा कि अगला कदम आरोपियों की संपत्ति कुर्क करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध से हुई आर्थिक लाभ को भी जब्त किया जाएगा। एसआईटी की योजना है कि इस कार्रवाई से तस्करी के पूरे नेटवर्क को कमजोर किया जा सके।

इस मामले में सहारनपुर के अशोक विहार कॉलोनी निवासी विशाल उपाध्याय की तहरीर पर कोतवाली क्षेत्र के चितरसारी शकरमंडी निवासी आकाश मौर्या, अरुण सोनकर, जमालपुर निवासी शिवम मौर्या, डालगर टोला निवासी अंकित कुमार श्रीवास्तव, संजीव कुमार चौरसिया, सुजानगंज के बलवरगंज निवासी सौरभ गुप्ता, अरुण प्रकाश मौर्या, बलुआघाट निवासी ओमप्रकाश मौर्या और सरायख्वाजा के सर्फराजपुर निवासी अनुप्रिया सिंह समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी केवल स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को बढ़ावा देती है। इस प्रकार की तस्करी से युवाओं को भी गंभीर खतरा होता है, क्योंकि यह नशा और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। एसआईटी की सक्रियता और गैर-जमानती वारंट की कार्रवाई यह संदेश देती है कि पुलिस और प्रशासन ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे।

स्थानीय प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि तस्करी के नेटवर्क को तेजी से पकड़ में लाया जा सके। एसआईटी का कहना है कि जांच जारी है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। यह कार्रवाई न केवल जौनपुर बल्कि पूरे राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

अब सवाल यह उठता है कि फरार आरोपियों को पकड़ने में कितना समय लगेगा और उनकी संपत्तियों की कुर्की प्रक्रिया कब शुरू होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया न्यायालय और कानून की पूर्ण पालना के तहत होगी और जल्द ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

जौनपुर में कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में यह कदम निश्चित रूप से प्रशासन और पुलिस के समर्पण को दर्शाता है। यह न केवल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश देता है, बल्कि आम जनता के बीच यह विश्वास भी बढ़ाता है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करेगा और कानून का पालन करने में कोई ढील नहीं बरतेगा।

कुल मिलाकर, जौनपुर का यह मामला राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। एसआईटी की तत्परता और गैर-जमानती वारंट की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अब अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

केंद्रीय बजट 2026-27

यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने वाला बजट है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2026-27 का बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को आगे बढ़ाने वाला बजट है।

केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार हुआ बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। इन तीन कर्तव्यों में पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना और इसे बनाए रखना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता निर्माण करना है। तीसरा कर्तव्य सबका साथ, सबका विकास के विजन के अनुरूप है और कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित सभी के विकास को प्राथमिकता देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में 'ग्यान' यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के साथ ही दिव्यांगजनों का आधार मजबूत होगा। इतना ही नहीं, समाज के सभी क्षेत्रों और प्रत्येक वर्ग को विकसित भारत के निर्माण में शामिल करने का बहुत ही सराहनीय दृष्टिकोण रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस केंद्रीय बजट से गुजरात को भविष्य में होने वाले फायदों का स्वागत करते हुए कहा कि लोथल और धोलावीरा का देश के पुरातात्विक विरासत क्लस्टर टूरिज्म डेवलपमेंट में समावेश हुआ है। इससे गुजरात में पर्यटन के माध्यम से 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार होगा। देश में 20 आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के लिए 10 हजार टूरिस्ट गाइड तैयार करने की योजना से गुजरात के आइकॉनिक टूरिस्ट स्थलों में भी स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने इसे शहरी विकास को नई दिशा देने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में शहरी उत्कर्ष के लिए प्रधानमंत्री की अटूट संकल्पबद्धता प्रतिबिंबित हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-टू और टियर-थ्री शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की घोषणा से राज्य के छोटे शहरों का सुव्यवस्थित विकास में तेजी आएगी।

देश में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के मामले में गुजरात के अग्रणी होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार का प्रशंसनीय

कदम है। इस बजट में म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए जिन प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है, उसका लाभ गुजरात की म्युनिसिपालिटीज को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह बजट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से लेकर बड़े उद्योगों, सभी के लिए प्रोत्साहक बजट है। उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है, साथ ही एमएसएमई पर भी बल दिया गया है, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बड़ा फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उद्योगों के लिए घोषित किए गए प्रोत्साहन भी गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करेंगे तथा टेक्सटाइल सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई 6 योजनाओं का लाभ भी राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, तीन केमिकल पार्क की घोषणा तथा बायोफार्मा इंडस्ट्रीज के लिए की गई 10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा का भी लाभ गुजरात के इन क्षेत्रों के उद्योगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा देश की क्रिटिकल मिनरल की जरूरत में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम साबित होगी।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में मुख्य औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, शोध संस्थानों, कौशल केंद्रों और रिहायशी परिसरों वाले इस सुनियोजित शैक्षणिक जोन से राज्यों के स्किल इकोसिस्टम को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए सूरत को पूर्वी भारत के दानकुनी के साथ जोड़ने की घोषणा लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की दिशा में एक 'मास्टर स्ट्रोक' साबित होगी। दक्षिण गुजरात के उद्योग जगत के पास अब पूर्वी भारत की ओर व्यापार करने के लिए 'हाई-स्पीड' कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जो राज्य के व्यापार और अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति देगी। इसके अलावा, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा से देश में जल मार्ग के क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में खादी, हथकरघा और हस्तकला को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके परिणामस्वरूप स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से संपर्क स्थापित करने और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण, कौशल विकास, प्रोसेस और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इतना ही नहीं, बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा करदाताओं का सम्मान किया है और उन्हें देश के विकास की प्रेरक शक्ति बताया है। इस बजट में भी करदाताओं के सम्मान का ख्याल रखते हुए ईमानदारी को बढ़ावा देने की दिशा में टैक्स जमा करने में हुई गलती को अपराध नहीं, बल्कि भूल मानते हुए सजा के बदले जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यह भी प्रशंसनीय है।

मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय और जनसामान्य सहित सभी के सर्वग्राही विकास, कल्याण तथा विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उनके योगदान को और अधिक प्रेरणा देने वाले बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- कर्तव्य भवन में तैयार हुआ बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है
- समाज के सभी क्षेत्रों और प्रत्येक वर्ग को 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र से कवर करने का सराहनीय दृष्टिकोण
- लोथल और धोलावीरा का पुरातात्विक विरासत क्लस्टर टूरिज्म डेवलपमेंट में समावेश होने से पर्यटन के माध्यम से गुजरात में 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार होगा
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-टू और टियर-श्री शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की घोषणा से राज्य के छोटे शहरों के सुव्यवस्थित विकास में तेजी आएगी
- एमएसएमई से लेकर बड़े उद्योग, यह सभी के लिए प्रोत्साहक बजट है
- टेक्सटाइल सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई 6 योजनाओं का लाभ गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा

कमर्शियल गैस महंगी, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत बरकरार

जीएनएस)। नई दिल्ली। फरवरी की शुरुआत के साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिली-जुली खबर सामने आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर महंगाई का दबाव बढ़ा है, लेकिन आम घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी ताजा दरों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1,740.50 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1,691.50 रुपये का था। इसी तरह कोलकाता में इसकी कीमत बढ़कर 1,844.50 रुपये हो गई है, जबकि जनवरी में यह 1,795 रुपये में उपलब्ध था। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1,692 रुपये तक पहुंच गए हैं और चेन्नई में इसकी कीमत 1,899.50 रुपये तय की गई है। अलग-अलग शहरों में दरों में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर उन व्यवसायों को प्रभावित करेगी, जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए बड़े पैमाने पर गैस का उपयोग करते हैं।

दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में यह सिलेंडर 853 रुपये में ही उपलब्ध रहेगा, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये बनी हुई है। लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, वाराणसी और पटना जैसे अन्य शहरों में भी घरेलू गैस के दाम जस के तस हैं। उल्लेखनीय है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार बदलाव 8 अप्रैल 2025 को किया गया था, इसके बाद से अब तक इसमें स्थिरता बनी हुई है।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के दामों के साथ-साथ टैक्स संरचना पर निर्भर करती हैं। जनवरी महीने में वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसका असर फरवरी के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में दिखाई दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को लागत की समीक्षा करती हैं और उसी आधार पर नए रेट घोषित किए जाते हैं, इसलिए कमर्शियल गैस के दामों में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसका असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान बढ़ी हुई लागत को किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहने से आम लोगों के मासिक बजट को फिलहाल राहत मिली है। कुल मिलाकर, फरवरी की शुरुआत में गैस की कीमतों में यह बदलाव एक बार फिर दिखाता है कि जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल का सीधा असर कमर्शियल सेक्टर पर पड़ता है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार और कंपनियों की नीति के तहत फिलहाल स्थिरता का लाभ मिल रहा है।

बजट 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया ऐतिहासिक बजट, पीएम मोदी बोले 'भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर' जबकि कांग्रेस ने लगाया पारदर्शिता का आरोप

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश के संसदीय इतिहास में नया रिकॉर्ड कायम किया है। 1959 से 1969 के बीच कुल दस बजट पेश करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुकी सीतारमण ने लगातार बजट पेश करने के मामले में पूर्व वित्त मंत्रियों चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी को पीछे छोड़ दिया है। इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला है। वहीं कांग्रेस ने बजट को पारदर्शी न बताया और कहा कि भाषण में योजनाओं और आवंटनों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

बजट 2026-27 को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर और विकसित बन रहा है, और सरकार ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बजट में देश के हर क्षेत्र और वर्ग के लिए योजना बनाई गई है। उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन में दो बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनसे इंडिया स्टैक और आईपी (बौद्धिक संपदा) के मामलों को बेहतर बनाया जाएगा। इसके तहत 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लागू की जाएगी, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की योजना का ऐलान किया गया, जो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है, जिसमें पूंजीगत खर्च में 24 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने बायोफार्मा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयों की कीमतें कम होंगी। इस बजट में जनगणना 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कोविड महामारी के कारण छह साल लेट होने के बाद अप्रैल से शुरू होगी। छात्रों और युवाओं के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने और कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपये देकर इसकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही एम्स के तीन नए संस्थानों की घोषणा की गई है।

बजट में कई वस्तुओं और सेवाओं को सस्ता करने के भी ऐलान किए गए हैं। इसमें बीड़ी, जूते, कपड़े निर्यात, CNG, विदेश यात्रा, बायोगैस, अवन, बैटरी, सात गंभीर बीमारियों की दवाइयां, शुगर की दवाइयां और मछुआरों के लिए निर्यात शामिल हैं। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर अब सजा नहीं होगी, केवल 30 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना लगेगा। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश और उत्पादन में टैक्स छूट दी जाएगी।

पीएम मोदी ने बजट पर कहा कि यह विकसित भारत का बजट है, जिसमें 2047 तक के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करता है और हर क्षेत्र और नागरिक के लिए स्पष्ट ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी बजट बताया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाषण पारदर्शी नहीं था और योजना आवंटनों की जानकारी स्पष्ट नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों के लिए बने बजट के रूप में देखा। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में उथल-पुथल मच गई। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई, बाजार 2,000 से अधिक अंक गिर चुका है। चांदी के दाम भी गिरावट के साथ 27 हजार रुपये कम हो गए। निवेशक और आम जनता दोनों ही बजट के प्रभावों को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। इस बजट में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपये की योजना बनाई है, टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास किया जाएगा, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए विशेष योजना लागू होगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, मेगा टेक्सटाइल पार्क, कंटेनर निर्माण और बायोफार्मा सेक्टर में निवेश जैसी घोषणाएं देश की ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था दोनों को सशक्त बनाएंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस परिवारों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और भारत को वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने पर है। उन्होंने संत रविदास को याद करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में देश का आर्थिक विकास निरंतर हुआ है और यह बजट आने वाले 25 वर्षों का रोडमैप तैयार करता है।

बजट पेश होने से पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की प्रति सौंपी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही और चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं। निर्मला सीतारमण ने हाथ से बुनी कांचीवरम सिल्क साड़ी पहनकर भारत की पारंपरिक बुनाई की विरासत का सम्मान किया।

संसद भवन में बजट पेश होने के दौरान सभी मंत्रियों और सचिवों की मौजूदगी रही। वित्त मंत्री ने Finance Bill 2026 भी पेश किया, जिसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत देश की अनुमानित आय और खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया। बजट का फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, रोजगार और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को ऐतिहासिक, प्रगतिशील और व्यापक विकास लक्ष्यों वाला बताया जा सकता है। सरकार ने इसे विकसित भारत का रोडमैप और आत्मनिर्भरता का प्रतीक करार दिया है। हालांकि, विपक्ष ने इसे पारदर्शिता और योजना आवंटन में कमी वाला बताया है। शेयर बाजार की प्रतिक्रिया और आम जनता की उम्मीदें इस बजट के कार्यान्वयन पर निगाहें बनाए हुए हैं।

"मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने चर्चगेट पर मीडिया को संबोधित किया

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर 1 फरवरी 2026 को चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर चल रहे जन-जागरूकता अभियान "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा जिम्मेदार रेल यात्रा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर श्री प्रदीप कुमार ने आम जनता से वैध टिकट खरीदकर जिम्मेदारीपूर्वक यात्रा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खरीदा गया टिकट सीधे तौर पर रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास, यात्री सुविधाओं के उन्नयन तथा सुरक्षा

प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में योगदान देता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि टिकट से प्राप्त राजस्व रेलवे के सुचारु संचालन, क्षमता विस्तार एवं सेवा सुधार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आगे विस्तार से बताते हुए महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने कहा कि नैतिक टिकटिंग एवं स्वैच्छिक अनुपालन रेलवे की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने जोर दिया कि यात्रियों का जिम्मेदार व्यवहार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण प्रयासों को सशक्त बनाता है और विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है।

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के साथ निरंतर संवाद, जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा सभी यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा कर इस अभियान को सफल बनाने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। सामूहिक जिम्मेदारी, अनुशासन और सहयोग के माध्यम से पश्चिम रेलवे यात्री विश्वास, परिचालन दक्षता और सेवा उत्कृष्टता को और सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है, जिससे विकसित भारत के व्यापक उद्देश्य में योगदान दिया जा सके।

फियो ने केंद्रीय बजट 2026–27 की सराहना की; एक मज़बूत निर्यात-सक्षम, उद्योग-अनुकूल और एमएसएमई -केंद्रित बजट के लिए सरकार को धन्यवाद: फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन

जीएनएस)। नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) केंद्रीय बजट 2026–27 का गर्मजोशी से स्वागत करता है और सरकार को एक साहसिक, दूरदर्शी और सुधार-उन्मुख बजट पेश करने के लिए बधाई देता है जो भारत की विकास यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से मज़बूत करता है, साथ ही भारतीय निर्यात, विनिर्माण और एमएसएमई की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को निर्णायक रूप से बढ़ाता है।

बजट पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने माननीय वित्त मंत्री और सरकार के प्रति निरंतर आर्थिक विकास, राजकोषीय विवेक, बुनियादी ढांचे के विस्तार और विश्वास-आधारित शासन के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये उपाय व्यापार और निवेश इकोसिस्टम को और अधिक ऊर्जा देंगे और निर्यातकों को एक स्थिर और अनुमानित नीतिगत माहौल प्रदान करेंगे।श्री रल्हन ने कहा, "केंद्रीय बजट 2026–27 स्पष्ट रूप से भारत की आर्थिक क्षमता को ठोस प्रदर्शन में बदलने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। विनिर्माण, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर मज़बूत ज़ोर—सार्थक कर और सीमा शुल्क सुधारों द्वारा समर्थित—भारतीय निर्यातकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक गहराई से और प्रतिस्पर्धी रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा।"

फियो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कपड़ा, रसायन, विमान घटक, निर्माण उपकरण और दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट जैसे उच्च-मूल्य और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करने के लिए सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करता है। 200 पुराने औद्योगिक समूहों के प्रस्तावित पुनरुद्धार, कई क्षेत्र-विशिष्ट पहलों के साथ, पैमाने, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात की तैयारी में सुधार की उम्मीद है। श्री रल्हन ने कहा कि उद्योग भारत के निर्यात पदचिह्न का विस्तार करने के लिए इन पहलों का सक्रिय रूप से लाभ उठाने के लिए तैयार है। व्यापार सुविधा उपायों का स्वागत करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि प्रमुख इनपुट पर शुल्क छूट, निर्यात समय-सीमा का विस्तार, विश्वसनीय निर्यातकों की पहचान और कारखाने परिसर से

निर्यात कार्गो की निकासी से लेनदेन लागत में काफी कमी आएगी, व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा और आपूर्ति-श्रृंखला दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "ये सुधार सीधे तौर पर निर्यातक के आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेंगे।"

फियो अध्यक्ष ने एमएसएमई के लिए सरकार के मज़बूत और सोचे-समझे सपोर्ट की भी तारीफ़ की, जिसमें तीन तरह के तरीके अपनाए गए हैं: 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड को बढ़ाना, टीआरईडी पर सीपीसीई की अनिवार्य ऑनबोर्डिंग, और इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। श्री रल्हन ने कहा, "एमएसएमई भारत के निर्यात इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। बजट में तरलता सहायता, इक्विटी समावेश और प्रोफेशनल कैपेसिटी-बिल्डिंग पर फोकस एमएसएमई को आगे बढ़ने, इनोवेशन करने और ग्लोबल चैंपियन बनने के लिए सशक्त करेगा।"

फियो ने सर्विस सेक्टर पर नए सिरे से ज़ोर देने का भी स्वागत किया—जिसमें आईटी, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, शिक्षा, डिज़ाइन, खेल और केयर इकोनॉमी शामिल हैं—जिसे सेफ हार्बर प्रावधानों और ज़्यादा टैक्स निश्चितता से सपोर्ट मिला है। ये उपाय, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, जलमार्गों और ऊर्जा सुरक्षा पर लगातार सार्वजनिक पूंजीगत खर्च के साथ मिलकर, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेंगे और एक वैश्विक सेवाओं और विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मज़बूत करेंगे।

बजट की दिशा में विश्वास व्यक्त करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के विज़न को प्राप्त करने के लिए एक मज़बूत नींव रखता है, जो विकास, समावेशन और राजकोषीय अनुशासन को संतुलित करता है। उन्होंने कहा "बजट वैश्विक बाजारों को एक मज़बूत और सकारात्मक संकेत भेजता है और एक विश्वसनीय, लचीले और आकर्षक व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में भारत की विश्वसनीयता को मज़बूत करता है। भारतीय उद्योग और निर्यातक इन पहलों के लाभों को अधिकतम करने और निर्यात-आधारित विकास में तेज़ी लाने के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।"